(ख) क्या जे० के० सिंथेटिक्स, कानपुर को ऋण देने वाले सेंट्रल बैंक आफ इंडिया सहित अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने उपर्युक्त ऋण की वसूली के लिए कडा रूख अपनाया है; यदि हां, तो कब और किन परिस्थितियों में एह एसा सब अपनाना पड़ा;

(ग) क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक को भी इस संबंध में कोई पत्र लिखा था; यदि हां तो क्या सरकार उस पत्र को सभा पटल पर रखेगी; और

(घ) क्या की गई कार्यवाही और इस प्रकार अपनाये गये कडे रूख के परिणामस्वरूप मै० जे० के० सिंथेटिक्स से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उक्त ऋण की वसूली करने में कोई प्रगति हुई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) निम्नांकित वित्तीय संस्थाओं और बैंकों ने मैसर्स जे० के० सिंथेक्टिस कानपुर को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है :–

वित्तीय संस्थाओं के नाम

1. भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम।
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम।
3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक।
4. भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक।
5. भारतीय यूनिट ट्रस्ट।
6. भारतीय जीवन बीमा निगम
7. आवास विकास तथा वित्त निगम।
8. राजस्थान निवेश तथा औद्योगिक निगम।
9. पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम।

बैंकों के नाम

1. भारतीय स्टेट बैंक।
2. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया।
3. स्टेट बैंक आफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर।
4. पंजाब नेशनल बैंक।
5. बैंक आफ़ राजस्थान।
6. इलाहाबाद बैंक।
7. बैंक आफ बड़ौदा।
8. अमेरिकन एक्सप्रैस।
9. बैंक आफ टोकियो।
10. हांगकांग तथा शंघाई बैंकिंग निगम।
11. ग्रिंडलेज बैंक।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों के उपबन्धों तथा लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम 1983 के अनुसरण में और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों के अनुसार बैंक और वित्तीय संस्थाए अपने अलग-अलग घटकों से सम्बन्धित सूचनाओं को प्रकट नहीं करते।

Delay in Passing SEBI Bill

1797. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "SEBI Bill not likely even in Parliament's Winter Session" published in the 'Financial Express' of 4th November, 1991;

(b) if so, what are the details thereof and reasons for not passing of the Securities and Exchange Board of India Bill which is hanging fire for over two years now; and

(c) by when Government propose to enact legislature?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a)

to (c) A proposal for giving Statutory powers to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) is under consideration.

कोंकण में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किसानों को ऋण देने से मना किया जाना

1798. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोंकण में देवरुख तहसील में बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों को ऋण देने से मना किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने किसानों को ऋण नहीं दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बैंक अधिकारी इस आधार पर ऋण देने से मना कर रहे हैं कि किसान समय पर ऋण वापस नहीं करते; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) बैंक ऑफ इंडिया सहित सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को किसानों को ऋणों की मंजूरी के संबंध में भारतीय बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों का पालन करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कृषि (जिसमें सम्बद्ध गति विधियां शामिल हैं) को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष वित्त अपने कुल निवल ऋण के 18% तक दे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को यह भी कहा है कि कृषि क्षेत्र सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण प्रवाह में रुकावट नहीं आनी चाहिये। फिर भी ऋणों की मंजूरी तथा संवितरण के बारे में बैंकों के कार्यकरण के विरुद्ध जब कभी कोई शिकायत सरकार को प्राप्त होती है भारतीय रिजर्व बैंक तथा संबंधित बैंक इसकी जांच करते हैं तथा सुधारात्मक उपाय करते हैं। संबंधित बैंकों का प्रबंधनभ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध उनके सेवा विनियमों के अनुसार कार्रवाई करते हैं।

Seizure of ATMs in Branches of some Foreign Banks in the Country

1799. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Directorate of Revenue Intelligence have seized and sealed bonds worth Rs. 8.56 crores for the release and use of Automatic Teller Machines;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the manner in which these machines are being imported and being used all over the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) During September, 1991. the officers of the Directorate of Revenue Intelligence served notices of seizure for 43 Automatic Teller Machines and 18 Automatic Machine Controllers collectively valued at Rs. 8.67 crores approximately which were installed in the various sites of Hongkong Bank and City Bank in Bombay, Delhi, Calcutta, Madras and Bangalore, as they had reason to believe that these machines had been imported by mis-declaring their description and value and were, therefore, liable for confiscation under the Customs Law. However, the machines were left in the custody of the respective Banks and simultaneously released provisionally so as not to impede their functioning. Hongkong Bank and City Bank have executed bonds for amounts of Rs. 6,10,50,000 and Rs. 3,44,,30,000 respectively for obtaining such provisional release.

(c) The imports of these machines was not made directly from the manufacturer but were arranged through a private indenter who alle-